डीजी परिपत्र संख्या - 68 /2016

जावीद अहमद

आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः दिसम्बर 17,2016

विषय : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ में योजित मिस रिट संख्या : 26791/2016 अजमल खान बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य तथा मिस बेंच संख्या : 26792/2016 महिमा पहवा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.11.2016 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 102/1/3/2016 - सीएक्स - 3 दिनांक 24.12.2016 अनुलग्नकों सहित आप समस्त को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित वाद संख्या : 26791/2016 अजमल खान बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं वाद संख्या : 26792/2016 महिमा पहवा बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 09.11.2016 को पारित निर्णय(छायाप्रति संलग्न) की प्रति में दिये गये आदेश का अनुपालन कराये जाने विषयक है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :-

"Restrictions on utilization and movement of vehicles in rallies or road shows in populated areas of the State more particularly as in the present case within the Municipal limits of the Lucknow."

उक्त सन्दर्भ में पर्यावरण अनुभाग-1 द्वारा निर्गत मुख्य सचिव के निर्देश पत्र संख्या : रिट - 94/55-पर्या0-2016-157(रिट)/2016 दिनांक 12.11.2016 की संलग्न प्रति के अनुक्रम में अवगत कराना है कि वायु गुणवत्ता में और सुधार हेतु प्रदेश के घनी आबादी वाले क्षेत्रों विशेषतया नगर निकाय सीमा में रैलियों/रोड शो में वाहनों के उपयोग एवं संचालन को प्रतिबन्धित किया जाये तथा यातायात को इस प्रकार नियन्त्रित किया जाये कि सड़को पर जाम की स्थिति न हो, ताकि सामान्य नागरिक के स्वास्थ्य पर प्रदूषणजनित प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

मैं चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का आप स्वयं अध्ययन कर लें तथा इन निर्देशों का समुचित पालन आपके एवं आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जाये। इस सम्बन्ध में कोई शिथिलता न बरती जाये यदि इन निर्देशों का अनुपालन करने में कोई ढिलाई संज्ञान में आती है तो उसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थों को विशेष रूप से अवगत करा दें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(जावीद अहमद)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4 अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच, उ0प्र0 लखनऊ।
5 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Court No. - 1

Case :- MISC. BENCH No. - 26791 of 2016
Petitioner :- Ajmal Khan
Respondent :- U.O.I. Thru. Secy.,Ministry Of Environment,Forest & Climate
Counsel for Petitioner :- Ajmal Khan (In Person)
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Verma,A.S.G.

AND

Case :- MISC. BENCH No. - 26792 of 2016
Petitioner :- Mahima Pahwa And Another {At:02:00 P.M.}
Respondent :- State Of U.P. Thru. Chief Secy.,Govt. Of U.P. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Ashish Chaturvedi,Akshat Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Gaurav Mehrotra,Mahesh Chandra,Shailendra Singh Chauhan,Sri Kumar Ayush

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Hon'ble Anil Kumar Srivastava-II,J.

Heard Sri Prashant Chandra, learned Senior Counsel, Sri Mohd. Arif Khan, learned Senior Counsel, Sri N.K. Seth, learned Senior Counsel, Sri Azmal Khan, learned counsel for the petitioners, learned Chief Standing Counsel, Sri Shailendra Singh Chauhan, learned counsel for the Lucknow Nagar Nigam, Lucknow and Sri S.B. Pandey for the Union of India.

The present proceedings in public interest were entertained and an order was passed yesterday in detail calling upon the authorities to provide information about the outcome of the exercise undertaken for measures that are to be adopted for ameliorating the situation that has arisen on account of accumulating hazarduous smog in and around the city of Lucknow.

Today, the learned Chief Standing Counsel has invited the attention of the Court to the directions issued by the National Green Tribunal yesterday which are to the following effect:-

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item No. 25 to 31 November	We have heard the matter at some length. Various senior officers of the State of Punjab, State of Rajasthan, State of

08, 2016	Uttar Pradesh and Delhi are present. They seek some time to answer the queries raised by the Tribunal, particularly in relation to implementation of five Judgments that had been passed by the Tribunal with regard to prevention and control of air pollution and adhere to the prescribed ambient Air Quality Standards. This has greater reference to the rising pollution of air in Delhi and the surrounding States. At their request we direct the matter be listed tomorrow for further submissions and orders. In the meanwhile we direct the following:- 1. No Stone Crusher would operate in NCR, Delhi and the aforesaid States concerned for a period of one week from today. There shall not be transportation whatsoever of any construction material. 2. All the officers of the respective Corporations, DDA, Municipal Corporation Committee and Corporations in the respective district of NCR, Delhi shall ensure that half of their staff is sent to field duty for inspection and ensuring that there is no burning of Municipal Solid Waste or any other waste; no pollution is generated by the construction activity and all the protection/ measures are taken as directed in the earlier Judgments of the Tribunal in relation to control of air pollution by construction activity and the concerned department staff shall also see there is not crop residue burning anywhere in these five states. The Judgment of the Tribunal in regard to the punitive directions, incentives, collection and utilization of agricultural residue are to be

implemented without default. Such staff of the Corporations will report back to their senior officer and submit report in regard to compliance and defaulters as afore-indicated.

3. We also prohibit all brick kiln operating in NCR, Delhi for a period of one week from today.

4. There shall not be any construction activity for a period of one week from today.

5. We direct Central Pollution Control Board to jointly prepare Ambient Air Quality Data currently; last one week and in future with the Pollution Control Board of the respective States. This data would not only give an Ambient Air Quality Standard but would also give apparent causes of pollution. Let this report be submitted to the Tribunal.

6. Proposals in relation to mechanized cleaning of dust from the roads shall be examined in terms of our Judgment. We should be informed about it by the authority concerned by tomorrow.

List these matters tomorrow i.e. on 09th November, 2016 at the 02:00 PM.

.....,CP
(Swatanter Kumar)

.....,JM
(Raghuvendra S. Rathore)

.....,EM
(Bikram Singh Sajwan)

The said issue has also been taken up before the Apex Court in respect of the National Capital Region and it is

informed that the matter is likely to be taken up on 10.11.2016.

The State Government had convened a meeting and the Chief Secretary of the State after deliberations has issued several directions calling upon the Principal Secretaries of the different concerned departments for taking appropriate steps in this regard that are extracted hereinunder:-

"मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश, शासन

पत्रांकः 1760/पीएसएमएस/2016
दिनांक : 08 नवम्बर, 2016

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण/औद्योगिक विकास/
सूक्ष्म लघु उद्योग/सिंचाई/नगर विकास/
राजस्व/गृह/पर्यावरण/लोक निर्माण/
आवास विकास/परिवहन

विगत कुछ दिनों से प्रदेश के कई शहरों व स्थानों पर वायु प्रदूषण जैसी स्थिति (SMOG) उत्पन्न हुई है जिससे जनसामान्य को कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थिति की रोकथाम हेतु तत्काल निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–

1. उ0प्र0 प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा तत्काल वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जनहित में जागरूकता एवं बचाव हेतु प्रमुख समाचार पत्रों में एडवायजरी निर्गत की जाय।

2. प्रदेश में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने हेतु नियमित रूप से प्रमुख शहरों में प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरद्ध अभियान चलाकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। आम नागरिकों की सुविधा हेतु बेहतर यातायात सुलभ कराने हेतु यातायात को निरन्तर गति देने की कार्यवाही की जाय जिससे ट्रैफिक जाम से वायु प्रदूषण पर रोक लगे।

(कार्यवाही– परिवहन विभाग)

3. शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर कूड़ा एकत्रित न होने पाये और एकत्रित कूड़े को किसी भी दशा में जलाया न जाये। शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की सफाई कराते समय यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि सड़कों से धूल न उठने देने के लिये आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव भी कराया जाये, ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। पॉलीथीन के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से कियान्वयन कराने हेतु ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। इस व्यवस्था की विषेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जनपदों में ध्यानपूर्वक व कड़ाई से लागू किया जाए।

(नगर विकास/औद्योगिक विकास विभाग)

4. प्रदेश की जनता को बेहतर वायु वातावरण उपलब्ध कराने हेतु आगामी 07 दिन के लिये वायु प्रदूषण फैलाने वाले स्टोन क्रेशर/ ईंट–भट्टों सहित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अर्थवर्क कार्य रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये। इस व्यवस्था की विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले जनपदों में ध्यानपूर्वक व कड़ाई से लागू किया जाए।

(गृह/आवास/राजस्व विभाग)

5. वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में यथासंभव प्रदूषण नियंत्रण यंत्र की स्थापना हेतु भरसक प्रयास किए जांय व प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय।

(औद्योगिक विकास एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग)

6. वायु प्रदूषण को रोकने हेतु यह सुनिश्चित कराया जाये कि किसानों द्वारा अपने खेतों में कृषि अपशिष्ट न जलाये जांय। किसानों को प्रेरित किया जाय कि वह कृषि अपशिष्ट का उपयोग खाद बनाने में अथवा अन्य उपयोग में करें।

(राजस्व एवं कृषि विभाग)

7. पर्यावरण विभाग द्वारा SMOG जैसी स्थितियों में CLOUD SEEDING की प्रकिया की उपयोगिता के बारे में भी शीघ्र विचार कर अवगत कराया जाएगा।

उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए व दिनांक 15.11.2016 तक Action Taken Report पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी जिसे पर्यावरण विभाग द्वारा संकलित कर विस्तृत आख्या का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

ह0 अपठनीय
(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे भी अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दुओं पर समन्वय कर कार्यवाही कराएं।

ह0 अपठनीय
(डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद)
स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव।"

The directions which have been given by the State Government therefore, need to be implemented forthwith and we accordingly direct the respective departments to issue necessary orders for execution without any further delay.

Apart from this, several other suggestions have been made by the learned counsel for the petitioners and from the aforesaid suggestions, we find that a useful hint can be taken for further improving the conditions by imposing certain conditions relating to:-

1. Prohibition of felling of trees and also compliance of any directions issued on the judicial side by the High Court. The learned Chief Standing Counsel shall inform the State Government about the said directions having been issued in order to enable the respective departments to enforce them strictly forthwith.

2. Directions to be issued by the State Government for restriction on utilization of fire crackers openly in public places during any forthcoming festivities including marriage ceremonies.

3. Restrictions on utilization and movement of vehicles in rallies or roadshows in populated areas of the State more particularly as in the present case within the Municipal limits of the Lucknow.

4. A forthwith review of any project or any plans for raising of constructions and colonies not only in and around Lucknow but throughout the State as well in order to ensure that the urban conglomeration is not ncentrated in a way so as to adversely affect public civil life and their health conditions contrary to population norms ratio.

The State Government shall take appropriate steps in this direction as well.

Apart from this, there is every likelihood of future problems arising on environmental issues and, therefore, it would be appropriate that the State Government also take into consideration such measures that have been adopted internationally for example, the one adopted as an integrated environmental programme in Australia as suggested by Sri Ajmal Khan during the course of his arguments which is available on the website. This is not to confine the suggestions of only one country but it would be appropriate that the State Government takes the help of an expert body or constitutes an expert body itself in the technical field of environment and pollution for suggesting such measures that may be necessary on a future vision of the plans that are required to be implemented to avoid any such further calamity.

The Municipal Corporation of Lucknow shall publish in the news items having wide circulations, the following numbers of the officials that are stated to be working to enable the public

at large to contact for information to remove garbage and undertake cleanliness doors:-

1.	Control Room, Nagar Nigam.	2307782, 2307783, 2307770
2.	Dr. P.K. Singh, Nagar Swasthya Adhikari,	9415607775
3.	Sri Pankaj Bhushan, Paryavaran Abhiyanta.	9415188957
4.	Sri Ashok Singh, Zonal Adhikari, Zone-1	9415609552
5.	Sri Sanjai Mamgai, Zonal Adhikari, Zone-2 and 5.	9415609556
6.	Sri Vinai Pratap Singh, Zonal Adhikari, Zone-3	9415000115
7.	Sri Anup Bajpai, Zonal Adhikari, Zone-4.	9415607791
8.	Smt. Binno Rizvi, Zonal Adhikari, Zone-6.	9415607919
9.	Sri Arvind Kumar Rai, zonal Adhikari, Zone-7.	9415609553
10	Sri Suraj Singh, Zonal Adhikari, Zone-8.	9415607774

We place the matter for Tuesday nex i.e., 15.11.2016 by which date the State Government shall further inform as to what steps have been taken and also intimate the Court as to what further directions have been issued by the National Green Tribunal or by the Apex Court in this regard for this Court for issuing necessary directions accordingly.

Order Date :- 9.11.2016
Rajneesh)

[Anil Kumar Srivastava-II,J.] [Amreshwar Pratap Sahi,J.]